भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *305
20 मार्च, 2026 को उत्तर के लिए

''प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए इस्पात की मांग''

*305 **डा. सुमेर सिंह सोलंकीः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी, 2026 तक प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं से उत्पन्न इस्पात की मांग की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के लिए इस्पात की आपूर्ति में घरेलू, लघु एवं मध्यम इस्पात उत्पादकों की भागीदारी के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) वर्ष 2024-2025 के दौरान घरेलू एवं वैश्विक इस्पात के मूल्यों में आए उतार-चढ़ाव का प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत तथा आपूर्ति की समय-सीमा पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने आपूर्ति की स्थिरता तथा मूल्य-पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक अवसंरचना योजना को घरेलू इस्पात की उत्पादन क्षमता के साथ समायोजित करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री एच.डी. कुमारास्वामी)**

(क) और (च): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी, संसद सदस्य द्वारा ''प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अंतर्गत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए इस्पात की मांग'' के संबंध में दिनांक 20.03.2026 को पूछे गए राज्यसभा तारांकित (*) प्रश्न संख्या *305 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च): भारत की क्रूड स्टील क्षमता 2013-14 के 102.26 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर 2024-25 में 200.33 एमटीपीए हो गई है, जो कि 95.90% की वृद्धि है। क्रूड स्टील का उत्पादन भी 2013-14 के 81.69 एमटीपीए से बढ़कर 2024-25 में 152.18 एमटीपीए हो गया है (अर्थात 86.28% की वृद्धि) जिससे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में निर्माण और आवास, ऑटोमोबाइल और अवसंरचना क्षेत्रों आदि में बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। यह मजबूत मांग भारत के विकसित भारत लक्ष्य में इस्पात की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है, जहाँ कीमतें मांग और आपूर्ति, वैश्विक बाजार की स्थितियों, कच्चे माल की कीमतों, लॉजिस्टिक्स, तथा विद्युत व ईंधन की लागत द्वारा निर्धारित होती हैं। लघु और मध्यम घरेलू इस्पात उत्पादकों सहित इस्पात कंपनियां, बाजार के प्रौद्योआर्थिक कारकों के आधार पर इन अवसंरचना परियोजनाओं को इस्पात की आपूर्ति करती हैं।

*****